

पी20 शिखर सम्मेलन पूरी दुनिया की विभिन्न संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम है: प्रधान मंत्री

...

P20 शिखर सम्मेलन उस भूमि पर हो रहा है जो न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है: प्रधान मंत्री

...

विभाजित विश्व मानवता के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता: प्रधान मंत्री

...

यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है। यह सभी के विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट से उबरना होगा और मानव-केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ना होगा: प्रधान मंत्री

...

प्रधान मंत्री ने 9वें G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन(P20) का उद्घाटन किया

...

भारत की जी-20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य-उन्मुख, निर्णायक और जन-केंद्रित रही है: लोक सभा अध्यक्ष

...

भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली लीडर्स डेक्लेरेशन को सर्वसम्मति से अपनाया जाना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है: लोक सभा अध्यक्ष

...

भारत की संसद के विशेष सत्र के पहले दिन नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने से पंचायत से संसद तक नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी: लोक सभा अध्यक्ष

...

भारत महिला सशक्तिकरण से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ चुका है: लोकसभा अध्यक्ष

...

डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से समावेशिता, पारदर्शिता और सुशासन का एक नया मॉडल विकसित हुआ: लोक सभा अध्यक्ष

...

लोक सभा अध्यक्ष ने 9वीं संसद 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया

...

नई दिल्ली; 13 अक्तूबर, 2023: प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यशोभूमि, नई दिल्ली में नौवें जी20 देशों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन (पी20) का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला उपस्थित थे।

G20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी; अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष, श्री दुआर्ते पचेको और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से जी20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में आए गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन पूरी दुनिया की सभी संसदीय प्रथाओं का एक 'महाकुंभ' है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख भी किया कि आज यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के पास विभिन्न देशों की संसदों का समृद्ध अनुभव है। इसके साथ ही श्री मोदी ने इस आयोजन के बारे में संतोष व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पी20 शिखर सम्मेलन उस भूमि पर हो रहा है जो न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। विश्व की सभी संसदों के प्रतिनिधियों में चर्चा और विचार-विमर्श के महत्व के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इतिहास में दर्ज संवाद और वाद-विवाद के सटीक उदाहरणों का उल्लेख भी किया।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि समय के साथ भारत की संसदीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ है और ये परम्पराएँ और सशक्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से भारत में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधान सभा चुनाव हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2019 का आम चुनाव, जिसमें उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी क्योंकि 600 मिलियन मतदाताओं ने इस चुनाव में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय 910 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे, जो पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं में से 70 प्रतिशत मतदान भारत के लोगों की संसदीय प्रथाओं में गहरी आस्था को दर्शाता है। 2019 के चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई। राजनीतिक भागीदारी के विस्तृत दायरे का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले आम चुनाव में 600 से अधिक राजनीतिक दलों ने भाग लिया और 10 मिलियन सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव का संचालन किया और इसके साथ ही मतदान के लिए 1 मिलियन मतदान केंद्र बनाए गए।

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों को संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित किए जाने के निर्णय की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्व-शासी संस्थानों में 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा "भारत आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा हाल ही में लिया गया निर्णय हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा"। प्रधानमंत्री ने भारत की संसदीय परंपराओं में नागरिकों के अटूट विश्वास पर प्रकाश डाला और इसकी विविधता और जीवंतता की बात भी की। विश्व के देशों की परस्पर संबद्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष और टकराव से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। यह सभी के विकास और कल्याण का समय है और हमें वैश्विक विश्वास के संकट से उबरना होगा और मानव-केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से देखना होगा" वैश्विक निर्णय लेने में व्यापक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल करने के प्रस्ताव के पीछे यही उद्देश्य था जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री ने पी20 के मंच में पैन अफ्रीका की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की।

अंत में प्रधान मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जनभागीदारी से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सहमति से चलता है। प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी संसदें और यह पी20 मंच भी इस भावना को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से इस दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली लीडर्स डेक्लरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक दृष्टिकोण और सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की वैश्विक मुद्दों पर प्रतिबद्धता और एकजुटता को दर्शाता है। श्री बिरला ने यह भी कहा कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य-उन्मुख, निर्णायक और जन-केंद्रित रही है। श्री बिरला ने कहा कि पी-20 शिखर सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक महत्व के विषयों और समकालीन चुनौतियों के समाधान के लिए संयुक्त संसदीय प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शिखर सम्मेलन के विषय, 'वसुधैव कुटुम्बकम् - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि यह धारणा भारत के सांस्कृतिक लोकाचार में निहित है और प्राचीन काल से ही भारत व्यापक रूप से विश्व के हितों और प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए समावेशी विकास को आगे बढ़ा रहा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत पर चलते हुए भारत ने हमेशा दुनिया को एक परिवार माना है, जिससे एकता, सहयोग और साझे भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का पता चलता है।

शिखर सम्मेलन के दौरान जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री बिरला ने बताया कि दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधि निम्नलिखित चार विषयों पर विचार-मंथन करेंगे: एसडीजी के लिए एजेंडा 2030: उपलब्धियां दर्शाना, प्रगति में तेजी लाना; (ii) सतत ऊर्जा परिवर्तन-हरित भविष्य का प्रवेश द्वार; (iii) महिला-पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाना- महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तक; और (iv) सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन।

शिखर सम्मेलन के एजेंडा के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है और भारत ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहले ही नीतिगत योजनाएँ तैयार कर ली हैं जिन पर भारत की संसद में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और भारत ग्रीन डेवलपमेंट और ग्रीन ट्रांजिशन को प्राथमिकता देते हुए सतत ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में कई पहलें कर रहा है। हाल ही में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि महिला सशक्तिकरण किसी भी देश के विकास का परिचायक है और अब भारत महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ गया है। श्री बिरला ने कहा कि अब पंचायत से लेकर संसद तक नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारत की

संसद के विशेष सत्र के पहले ही दिन "नारी शक्ति वंदन विधेयक" पारित कर दिया गया, जिसके माध्यम से अब लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास 21वीं सदी की दुनिया में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा।

सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के विषय पर अपने विचार रखते हुए, श्री बिरला ने कहा कि इन प्लेटफार्मों के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल रहे हैं। श्री बिरला ने यह भी कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से समावेशिता, पारदर्शिता और सुशासन का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि डीबीटी, यूपीआई जैसे डिजिटल इंटरवेंशन से देश के सर्वांगीण विकास और समावेशी शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से आज जनता की संसद तक बेहतर पहुँच है।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष, श्री दुआर्ते पचेको ने लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और भारत की संसद द्वारा गर्मजोशी से किए गए आतिथ्य-सत्कार के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल नेतृत्व के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी बधाई दी। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए, श्री पचेको ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में भारत की संसद की प्रमुखता और प्रासंगिकता को देखते हुए पी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में कोई संदेह नहीं। विश्व शांति के मूलभूत मूल्य के महत्व के बारे में बात करते हुए, श्री पचेको ने कहा कि सांसदों को दुनिया के सभी हिस्सों में शांति की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति के बिना दुनिया सतत विकास जैसे अन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। श्री पचेको ने कहा कि चूंकि सांसद चर्चा और संवाद के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने की बात को समझते हैं, इसलिए वैश्विक मुद्दों के समाधान में उन्हें अधिक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इस दिशा में आईपीयू और पी20 के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ द्विपक्षीय भेंट

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने पी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कोरिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के स्पीकर, श्री किम जिन-प्यो से भेंट की। श्री बिरला ने उन्हें बताया कि वर्ष 2023 भारत और कोरिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है। राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। श्री बिरला ने इस बात का उल्लेख भी किया कि बौद्ध भिक्षुओं की यात्राओं और ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से बौद्ध धर्म ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संसदीय सहयोग को और बढ़ाए जाने पर जोर दिया।